Proposal to Review Dearness Allowance policy

601. SHRI D. D. DESAI: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to review the Dearness Allowance policy in view of the mounting costs of increases in D.A. to its employees and the employees of public sector undertakings;

(b) whether any rationalisation of D.A. rates as between various departments and public sector undertakings will be attempted as a result of this review; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUAR ULLAH): (a) to (c). The reference apparently is to the action taken by the Government on the recommendations of the Study Group on Wages, Incomes and Prices (Bhoothalingam Committee) set up by the Government. So far as Dearness Allowance is concerned, the Study Group had pointed out that the present heterogeneity of Dearness Allowance formulae in different sectors of employment had resulted in distortions, anomalies and narrowing of wage differentials in all sectors. The Committee was, therefore, of the view that there was need for a single national corrective formula to compensate for the rise in the cost of the essential consumer basket. It had accordingly recommended that it would be appropriate to link future Dearness Allowance increases to cost of living on a uniform basis with reference to the All India Average Consumer Price Index for industrial Workers (General) 1960=100).

Government have not yet taken any decisions on the recommendations of the Study Group.

राष्ट्रीय आय की विकास दर

603. श्री युवराज : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय आय की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या दो वर्षों तक मुद्रा परिचालन में निरन्तर वृद्धि होने के बावजूद मूल्य स्तर स्थिर रहा है ;

(ग) क्या औद्योगिक उत्पादन की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है; और

(घ) यदि हां, तो खाद्यान्नों की क्या स्थिति है और विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भण्डार में कितनी वृद्धि हुई है और गन्ना, चाय, काफी और कपास के उत्पादन की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) राष्ट्रीय आय अपरिवर्तित (1970-71) रहते हुए, कीमतों में 1977-78 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि इसकी तुलना में 1976-77 में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ख) जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में 1977-78 में 10.8 प्रतिशत का विस्तार हुआ और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक (31 मार्च से 29 दिसम्बर, 1978 तक) 9.2 प्रतिशत का विस्तार हुआ। इसके बावजूद थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100) में मार्च, 1977 और जनवरी 1979 के बीच मामूली घटबढ़ हुई। सूचक अंक का स्तर जुलाई, 1977 में अधिकतम (188.7) और अप्रैल, 1978 में निम्नतम (182.4) था।

(ग) हाल के महीनों में औद्योगिक उत्पादन की गति बहुत संतोषजनक रही। 1978-79 में औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि इसकी तुलना में 1977-78 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(घ) 1977-78 में खाद्यान्न का उत्पादन 12.56 करोड़ मेट्रिक टन का था और 1978-79 में भी इतना ही उत्पादन होने की संभावना है। दिसम्बर, 1978 के अन्त में सरकार के पास 1.74 करोड़ मेट्रिक टन का भंडार था। गन्ने का उत्पादन भी लगभग पूर्ववर्ती वर्ष जितना अर्थात् 1.88 करोड़ मेट्रिक टन (गुड़ के रूप में) होने की संभावना है। कपास का उत्पादन लगभग 0.73 करोड़ गांठें होने की संभावना है। जब कि इसकी तुलना में 1977-78 में 0.71 करोड़ गांठों का उत्पादन हुआ था। चाय का उत्पादन जो 1977 में 56.08 करोड़ किलोग्राम था 1978 में बढ़ कर , 57.09 करोड़ किलोग्राम हो गया। 1977-78 में 122.3 हजार मेट्रिक टन काफी के उत्पादन की संभावना है जबकि इसकी तुलना में पूर्ववर्ती वर्ष में 102 3 हजार मेट्रिक टन काफी का उत्पादन हुआ था। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में (सोने और एस० डी० आर० को छोड़ कर) 1977-78 में 1637 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी, जब कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में उसमें 582 करोड़ रुपये की और वृद्धि हो गई है।